



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 51]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 10, 2006/माघ 21, 1927

No. 51]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 10, 2006/MAGHA 21, 1927

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 फरवरी, 2006

सा.का.नि. 57(अ).—विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 (1946 का 31) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा विदेशियों विषयक (अधिकरण) आदेश, 1964 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इस आदेश को विदेशियों विषयक (अधिकरण) संशोधन आदेश, 2006 कहा जाएगा।

(2) यह इसके सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावी होगा।

2. विदेशियों विषयक (अधिकरण) आदेश, 1964 में :—

(क) पैराग्राफ की क्रम संख्या बदलकर उसे उप-पैराग्राफ (1) कर दिया जाएगा और इस प्रकार उप-पैराग्राफ (1) करने के बाद उसके नीचे निम्नलिखित उप-पैराग्राफ जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

“(2) यह आदेश असम राज्य के अलावा सम्पूर्ण भारत में लागू होगा।”

(ख) पैराग्राफ 2 में, उप-पैराग्राफ (1क) विलोपित कर दिया जाएगा;

(ग) पैराग्राफ 3 में, उप-पैराग्राफ (1क) विलोपित कर दिया जाएगा।

[सं. 11012/47/2005-एनई. IV]

राजीव अग्रवाल, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : मूल सं. सा.का.नि. 140, भारत के असाधारण राजपत्र में दिनांक 23-9-1964 को प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th February, 2006

G.S.R. 57(E).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Foreigners Act, 1946 (31 of 1946), the Central Government hereby makes the following amendments in the Foreigners (Tribunal) Order, 1964, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) This Order may be called the Foreigners (Tribunal) Amendment Order, 2006.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Foreigners (Tribunal) Order, 1964 :—

(a) paragraph 1 shall be renumbered as sub-paragraph (1) thereof and after sub-paragraph (1) as so renumbered the following sub-paragraph shall be inserted, namely :—

“(2) This Order shall apply to the whole of India except the State of Assam.”

(b) In paragraph 2, sub-paragraph (1A) shall be omitted;

(c) In paragraph 3, sub-paragraph (1A) shall be omitted.

[No. 11012/47/2005-NE.IV]

RAJIV AGARWAL, Jt. Secy.

Footnote : The original No. G.S.R. 140 was published on 23-9-1964 in the Extraordinary Gazette of India.

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 फरवरी, 2006

सा.का.नि. 58(अ).—विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 (1946 का 31) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा निम्नलिखित आदेश जारी करती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और विस्तार :— (1) इस आदेश को विदेशियों विषयक (असम के लिए अधिकरण) आदेश, 2006 कहा जाएगा।

(2) यह असम राज्य पर लागू होगा।

2. अधिकरणों का गठन :— (1) केन्द्रीय सरकार अथवा इस संबंध में विनिर्दिष्ट अन्य कोई प्राधिकरण, आदेश द्वारा, इस आशय का प्रश्न कि कोई व्यक्ति विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 (1946 का 31) की परिभाषा में विदेशी है अथवा नहीं, इस आशय के लिए गठित अधिकरण को उसकी राय जानने के लिए भेजेगा।

(2) नागरिकता नियम, 1956 के नियम 16 (च) के उप-नियम (1) के अन्तर्गत नियुक्त पंजीयन प्राधिकारी अधिकरण को इस आशय का प्रश्न भेजेगा कि भारतीय मूल के किसी व्यक्ति को नागरिकता अधिनियम, 1955 (1955 का 57) की धारा 6 (क) की उप-धारा (iii) के अन्तर्गत किन्हीं अपेक्षाओं का अनुपालन करना होगा अथवा नहीं।

(3) इस अधिकरण में केन्द्रीय सरकार द्वारा उचित माने जाने वाली संख्या में न्यायिक अनुभव वाले व्यक्तियों की नियुक्ति की जा सकेगी।

(4) यदि अधिकरण में दो अथवा अधिक सदस्य होंगे तो उनमें से एक अधिकरण का अध्यक्ष होगा।

(5) उप-पैराग्राफ (1) के अन्तर्गत अधिकरण का गठन किये जाने तक, विदेशियों विषयक (अधिकरण) आदेश, 1964 के अन्तर्गत गठित अधिकरण को ही इस आदेश के प्रयोजनार्थ अधिकरण माना जाएगा।

3. प्रश्नों के निपटान की प्रक्रिया :— (1) अधिकरण पैराग्राफ 2 के उप-पैराग्राफ (1) के अन्तर्गत प्राप्त प्रश्न के संबंध में यह विचार करेगा कि उसके संबंध में कार्रवाई करने के संबंध में क्या पर्याप्त आधार मौजूद है और यदि अधिकरण इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि प्रथम दृष्टया मूल तथ्य सिद्ध है तो वह प्रश्न से संबंधित व्यक्ति को वह प्रश्न और कथित तौर पर विदेशी कहे जाने के मुख्य आधार की एक प्रति भेजेगा और अभ्यावेदन देने तथा अपने मामले में साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए उस व्यक्ति को पर्याप्त अवसर प्रदान करेगा और प्रस्तुत किए गए साक्ष्य पर विचार करने तथा सुनवाई के इच्छुक व्यक्ति को सुनवाई करने के पश्चात् अधिकरण अपनी राय आदेश में इस संबंध में विनिर्दिष्ट अधिकारी या प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा।

(2) पैरा 2 के उप-पैरा (2) के अन्तर्गत भेजे गये प्रश्न के संबंध में अपनी राय देने से पहले अधिकरण, जिस व्यक्ति के संबंध में राय मांगी गई है उस व्यक्ति को अपने मामले में अभ्यावेदन देने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करेगा।

(3) इस आदेश के प्रावधानों के अधधीन, इस अधिकरण के पास अपनी प्रक्रिया विनियमित करने की शक्ति होगी।

4. अधिकरण की शक्ति :— अधिकरण को निम्नलिखित मामलों में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अंतर्गत किसी मामले की सुनवाई करते समय सिविल कोर्ट की शक्तियां प्राप्त होंगी, अर्थात् :—

(ख) किसी भी व्यक्ति को सम्मन जारी करना और उपस्थित होने के लिए बाध्य करना और उसे शपथ दिलाकर उसके साथ जिरह करना।

(ग) किसी भी दस्तावेज को खोज और उपलब्धता की मांग करना।

(घ) किसी भी गवाह के साथ जिरह के लिए कमीशन में भेजना।

[सं. 11012/47/2005-एनई-IV]

राजीव अग्रवाल, संयुक्त सचिव

## NOTIFICATION

New Delhi, the 10th February, 2006

G.S.R. 58(E).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Foreigners Act, 1946 (31 of 1946), the Central Government hereby makes the following Order, namely :—

1. Short title and extent.— (1) This Order may be called the Foreigners (Tribunals for Assam) Order, 2006.

(2) It shall apply to the State of Assam.

2. Constitution of Tribunals :— (1) The Central Government or any authority specified in this regard shall, by order, refer the question as to whether a person is or is not a foreigner within the meaning of the Foreigners Act, 1946

(31 of 1946) to a Tribunal to be constituted for the purpose, for its opinion.

(2) The registering authority appointed under sub-rule (1) of rule 16F of the Citizenship Rules, 1956 shall refer to the Tribunal the question whether a person of Indian origin complies with any of the requirements under sub-section (3) of Section 6A of the Citizenship Act, 1955 (57 of 1955).

(3) The Tribunal shall consist of such number of persons having judicial experience as the Central Government may think fit to appoint.

(4) Where the Tribunal consists of two or more members, one of them shall be appointed as the Chairman thereof.

(5) Till any Tribunal is constituted under sub-paragraph (1), the Tribunals constituted under the Foreigners (Tribunal) Order, 1964 shall be deemed to be Tribunals for the purposes of this Order.

**3. Procedure for disposal of questions.**—(1) The Tribunal, upon receipt of a reference under sub-paragraph (1) of paragraph 2, shall consider whether there is sufficient ground for proceeding and if the Tribunal is satisfied that basic facts are *prima facie* established, it shall serve on the person to whom the question relates, a copy of the main grounds on which he is alleged to be a foreigner and give him a reasonable opportunity of making a representation and producing evidence in support of his case and after considering such evidence as may be produced and after hearing such persons as may desire to be heard, the Tribunal shall submit its opinion to the officer or authority specified in this behalf in the order of reference.

(2) The Tribunal shall, before giving its opinion on the question referred to in sub-paragraph (2), of paragraph 2, give the person in respect of whom the opinion is sought, a reasonable opportunity to represent his case.

(3) Subject to the provisions of this Order, the Tribunal shall have power to regulate its own procedure.

**4. Power of Tribunals.**— The Tribunal shall have the powers of a civil court while trying a suit under the Code of Civil Procedure, 1908 in respect of the following matters, namely :—

- (b) summoning and enforcing the attendance of any person and examining him on oath;
- (c) requiring the discovery and production of any document;
- (d) issuing commissions for the examination of any witness.

[No. 11012/47/2005-NE. IV]

RAJIV AGARWAL, Jt. Secy.